

भारत का वित्तीय
The Gazette of India
असाधारण • GOVT OF INDIA
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 275] नई दिल्ली, शनिवार, जून 28, 1980/अष्टावृ 7, 1902

No. 273] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 28, 1980/ASADHA 7, 1902

इस भाग में भिन्न दृष्ट संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के लिए रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

एक संग्रहालय

अधिकृत

नई दिल्ली, 28 जून, 1980

का. अ. 422(अ).—वांश्वीय सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा अधिकार है कि लाइब्रेरी प्रदातों सम्बन्धी उद्योग में नगो भारतीय लाइब्रेरी नियम को, जिसे औद्योगिक विद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 वा 14) की प्रथम अनुसूची गं निर्दिष्ट किया गया है, उक्न अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी मेंदा विविध किया जाना चाहिए ।

अतः, अब, औद्योगिक विद्यालय अधिनियम, 1947 (1947 वा 14) की धारा 2 के खण्ड (ह) के उपखण्ड (6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय स्थायी निगम को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए तत्काल प्रभाव से छ: मास की कालावधि के लिए लोक उपयोगी सेवा घोषित करती है ।

[संख्या एस. -11017/6/80-डी. 1 ए.]

कृ. म. सेठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th June, 1980

S.O. 474(E).—Whereas the Central Government is satisfied that the public interest requires that the Food Corporation of India engaged in the foodstuffs industry which is specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), should be declared to be a public utility service for the purposes of the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby declares with immediate effect the Food Corporation of India to be a public utility service for the purposes of the said Act for a period of six months.

[No. S-11017/6/80-D.I.A.]

(Miss) M. SETH, Jt. Secy.